



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 65-2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 11, 2019 (CHAITRA 21, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अप्रैल, 2019

**संख्या 54/जीएसटी-2.-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।  
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम प्रथम अप्रैल, 2019 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 41 में, उपनियम (1) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी और 29 मार्च, 2019 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

**"व्याख्या:-** इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, इसके द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है कि "आस्तियों का मूल्य" से अभिप्राय है, कारबार की संपूर्ण आस्तियों का मूल्य, चाहे उन पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है या नहीं।"

- उक्त नियमों में, नियम 42 में,-

(क) उप-नियम (1) में,-

क. खण्ड (च) में, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्,-

**"व्याख्या:** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाली सेवाओं के प्रदाय के मामले में, T4 का मूल्य निर्माण के चरण के दौरान शून्य होगा क्योंकि समापन प्रमाण पत्र के जारी किये जाने या परियोजना के प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, की तिथि को या उसके पहले बुक किये गये अपार्टमेंट और जो उक्त तिथि तक बुक न किये गये हों, के निर्माण के लिए इनपुट और इनपुट सेवाओं का उपयोग एक ही प्रकार का होगा।";

ख. खण्ड (छ) में, "प्ररूप जीएसटीआर 2" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सारांश स्तर पर" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

ग. खण्ड (ज) में, "(छ)"कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "(च)" कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. खण्ड (झ) में, -

i. विद्यमान परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1419)

"परंतु अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाली सेवाओं के प्रदाय के मामले में, किसी कर अवधि के लिए 'ई/एफ' का मूल्य, निम्नानुसार ई तथा एफ के मूल्य को हिसाब में लेते हुए प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग संगणित किया जाएगा;

ई= अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र, जिसका निर्माण अपार्टमेंट्स के कर जमा कुल कार्पेट क्षेत्र से मुक्त है, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, किंतु समापन प्रमाण पत्र या प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, के जारी होने के बाद बेचे जाने के लिए प्रोत्साहक द्वारा परिलाक्षित किया गया हो;

एफ = परियोजना में अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र;

**व्याख्या 1:** कर अवधि, जिसमें समापन प्रमाण-पत्र जारी करना या परियोजना का प्रथम अधिभोग होता है, में, ई के मूल्य में अपार्टमेंट्स, जो समापन प्रमाण पत्र जारी करने या परियोजना का प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, की तिथि तक बुक नहीं किए गए हैं, का कुल कार्पेट क्षेत्र भी शामिल होगा ;

**व्याख्या 2:** हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, यथा संशोधित, के पैराग्राफ 4 में व्याख्या (iv) के दृष्टिगत "ई" के मूल्य की संगणना के लिए उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट क्षेत्र को भी हिसाब में लिया जाएगा, जिसके निर्माण पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, यथा संशोधित, की सारणी की क्रम संख्या 3 के सामने मद (i), (ik), (ix), (ig) या (ig) के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान योग्य है:";

- ii. विद्यमान परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, "परंतु यह और कि" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

ड. खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ठ) 'सी3', 'डी1' और 'डी2' राशि की केंद्रीय कर, राज्य कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से की जाएगी;"

च. खण्ड (ड) में, "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख में या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रिवर्सड किया जाएगा" शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "इनपुट कर प्रत्यय" शब्दों के स्थान पर, "उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाली सेवाओं के प्रदाय के मामले को छोड़कर, इनपुट कर प्रत्यय" शब्द, अंक तथा कोष्ठक को प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ग) उप-नियम (2) में, खण्ड (क) में, "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की, उस मास में के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ा जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटीआर-3ख में या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पंजीत व्यक्ति द्वारा रिवर्सड किया जाएगा" शब्द, चिह्न, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(घ) उप नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(3) अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाली सेवाओं के प्रदाय के मामले में, उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित इनपुट कर की अंतिम गणना प्रत्येक चालू परियोजना या परियोजना, जो प्रथम अप्रैल, 2019 को या के बाद शुरू हुई है के लिए, की जाएगी, ऐसी प्रत्येक परियोजना से संबंधित, जिनमें प्रथम अप्रैल, 2019 को कर में दरों के परिवर्तन के कारण, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट कर प्रत्यय का कोई बदलाव नहीं आया है प्रथम जुलाई, 2017, या परियोजना के शुरू होने की संपूर्ण अवधि, जो भी बाद में है, से लेकर परियोजना के पूरा होने या प्रथम अधिभोग की तिथि, जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें समापन प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या परियोजना का प्रथम अधिभोग लिया गया हो, के आगामी वित्तीय वर्ष के सितम्बर मास तक, उक्त उप-नियम में विहित रीति में की जाएगी, इस संशोधन के साथ कि ई/ एफ के मूल्य की गणना निम्नलिखित ई और एफ का मूल्य लेते हुए की जाएगी:

ई = अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के कर जमा कुल कार्पेट क्षेत्र से छूट देता है, जिसका निर्माण टैक्स से छूट नहीं देता है, किंतु जिसे समापन प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि या परियोजना के प्रथम अधिभोग तक बुक नहीं किया गया है जो भी पहले हो:

एफ = परियोजना में अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र;

तथा,—

(क) जहां 'डी 1' और 'डी 2' के संबंध में अंतिम रूप से संगणित राशियों का कुल योग 'डी 1' और 'डी 2' के संबंध में उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित राशियों के कुलयोग से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष, जिसमें समापन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है या परियोजना का प्रथम अधिभोग होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर मास तक, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रिवर्सड किया जाना है, और उक्त व्यक्ति धारा 50 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से भुगतान की तिथि तक; या

(ख) जहां "डी 1" और "डी 2" के संबंध में उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित राशि का कुल योग "डी 1" और "डी 2" के संबंध में अंतिम रूप से संगणित राशि से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्यय के रूप में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें समापन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है या परियोजना का प्रथम अधिभोग होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के मास तक की विवरणी में किया जायेगा।

(4) अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाली सेवाओं के प्रदाय के मामले में, उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित इनपुट कर की अंतिम गणना आवासीय भू-सम्पदा परियोजना के अलावा प्रत्येक परियोजना में वाणिज्यिक भाग के लिए की जाएगी, जिनमें प्रथम अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट कर प्रत्यय का बदलाव आया है, परियोजना के शुरू होने की तिथि या प्रथम जुलाई, 2017, जो भी बाद में है, से लेकर परियोजना के पूरा होने या प्रथम अधिभोग की सम्पूर्ण अवधि, जो भी पहले हो, उस वित्तीय वर्ष जिसमें समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या परियोजना का प्रथम अधिभोग लिया गया हो, के अग्रिम वित्तीय वर्ष के सितम्बर मास के लिए, विवरणी के प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व, निम्नलिखित रीति में की जाएगी, —

(क) परियोजना में वाणिज्यिक हिस्से पर समान क्रेडिट की कुल राशि (सी3<sub>aggregate\_comm</sub>) की गणना निम्नानुसार की जाएगी,

सी3<sub>aggregate\_comm</sub> = [उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित सी3 की राशियों की कुल राशि प्रथम जुलाई, 2017 से शुरू होकर 31 मार्च, 2019 से शुरू होने वाली कर अवधि के लिए  $\times (A_C / A_T)$ ][उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित सी3 की राशियों की कुल राशि जो प्रथम अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाली कर अवधि के लिए परियोजना के पूरा होने तक अथवा परियोजना के प्रथम अधिभोग की तिथि तक, जो भी पहले हो,

जहां, —

$A_C$  = परियोजना में वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र

$A_T$  = परियोजना में सभी अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र

(ख) परियोजना में वाणिज्यिक हिस्से पर अंतिम पात्र समान क्रेडिट की राशि (सी3<sub>final\_comm</sub>) की गणना निम्नानुसार की जाएगी

सी3<sub>final\_comm</sub> = सी3<sub>aggregate\_comm</sub>  $\times$  (ई / एफ)

जहां, —

ई = वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र जो समापन प्रमाण पत्र जारी होने या परियोजना के प्रथम अधिभोग की तिथि जो भी पहले हो, तक बुक नहीं किया गया है।

एफ =  $A_C$  = परियोजना में वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र

(ग) जहां सी3<sub>aggregate\_comm</sub> सी3<sub>final\_comm</sub> से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर माह में, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रिवर्सड की जाएगी, जिसमें समापन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है या परियोजना का प्रथम अधिभोग होता है और उक्त व्यक्ति, अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से शुरू होने वाली अवधि के लिए भुगतान की तिथि तक धारा 50 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(घ) जहां, सी3<sub>final\_comm</sub>, सी3<sub>aggregate\_comm</sub> से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा, उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें समापन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या परियोजना का प्रथम अधिभोग होता है, की समाप्ति के बाद के सितंबर के मास के लिए उसकी विवरणी में किया जायेगा।

(5) उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित इनपुट कर की अंतिम रूप से गणना उन आवासीय भू-सम्पदा परियोजना के पूरा होने या प्रथम अधिभोग पर, जिनमें प्रथम अप्रैल, 2019 को हुए कर में दरों के परिवर्तन के कारण, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, यथा संशोधित, के अनुसार, इनपुट कर प्रत्यय का बदलाव आया है, करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(6) जहां किसी भी इनपुट या इनपुट सेवा का उपयोग एक से अधिक परियोजना के लिए किया जाता है, ऐसे इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय प्रत्येक परियोजना को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और प्रत्येक परियोजना से संबंधित क्रेडिट रिवर्सल उप-नियम (3) के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।”।

4. उक्त नियमों में, नियम 43 में, —

(i) उप नियम (1) में, —

(क) खण्ड (क) में, "प्ररूप जी.एस.टी.आर. 2" शब्दों और अंकों के बाद, "और प्ररूप जी.एस.टी.आर.—3ख" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख)— खण्ड (ख) में,—

(i) "प्ररूप जी.एस.टी.आर. —2" शब्दों और अंकों के बाद, "और प्ररूप जी.एस.टी.आर.—3ख" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) अंत में, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्: —

**“व्याख्या:** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाली सेवाओं के प्रदाय के मामले में, पूँजीगत मालों के संबंध में इनपुट कर की राशि जिसका उपयोग या उपयोग के लिए आशयित विशेष रूप से या रियायती प्रदाय से भिन्न अन्य प्रदाय प्रभावित करने के लिए, जिसमें शून्य दर प्रदाय आता है, निर्माण चरण के दौरान शून्य होगा, चूंकि पूँजीगत मालों का उपयोग समापन प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि या परियोजना का प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, से पहले बुक किए गए अपार्टमेंट के निर्माण के लिए तथा जिन्हें उक्त तिथि तक बुक नहीं किया गया हो के लिए समान तौर पर किया जाएगा।”

(ग) खण्ड (छ) में, —

(i) “‘एफ’ कर अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कुल आवर्त है” शब्दों के स्थान पर, “‘एफ’ कर अवधि के दौरान राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कुल आवर्त है” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) विद्यमान परंतुक से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खण्ड (ख) के अधीन आने वाली सेवाओं के प्रदाय के मामलों में, कर अवधि के लिए ‘ई/एफ’ का मूल्य प्रत्येक परियोजना के लिए अलग अलग, ई और एफ को निम्नानुसार हिसाब में लेते हुए संगणित किया जाएगा:

ई = अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र, जिसका निर्माण अपार्टमेंट के कर जमा कुल कार्पेट क्षेत्र से छूट देता है, जिसके निर्माण पर टैक्स से छूट नहीं है, किंतु जिसे परियोजना के समापन प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि या प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, तक बुक नहीं किया गया है,;

एफ = परियोजना में अपार्टमेंट का कुल कार्पेट क्षेत्र;

**व्याख्या 1:** कर अवधि में, जिसमें समापन प्रमाण पत्र जारी करने या परियोजना का प्रथम अधिभोग होता है, ई के मूल्य में अपार्टमेंट का कुल कार्पेट क्षेत्र भी शामिल होगा, जो समापन प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि या परियोजना के प्रथम अधिभोग जो भी पहले हो तक बुक नहीं किया गया है;

**व्याख्या 2:** हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, के पैराग्राफ 4 की व्याख्या (iv) के दृष्टिगत “ई” के मूल्य की गणना में उस अपार्टमेंट्स के कार्पेट क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा अपार्टमेंट्स के कार्पेट क्षेत्र जिसके निर्माण पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम संख्या 3 के सामने के मद (i), (ik), (ix), (ig) या (ig) में विनिर्दिष्ट दर से कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान योग्य है।”;

(iii) विद्यमान परंतुक में, “परंतु” शब्द के स्थान पर, “परन्तु यह और कि” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) खण्ड (ज) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्: —

"(झ) टीए की राशि की गणना केंद्रीय कर, राज्य कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए अलग अलग की जाएगी और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में घोषित की जाएगी।"

(ii) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(2) अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 5 (ख) के अधीन की गई सेवाओं के प्रदाय के मामले में, छूट दिये गये प्रदाय (टीए<sup>final</sup>) के कारण सामान्य क्रेडिट की राशि की गणना परियोजना के शुरू होने से सम्पूर्ण अवधि के लिए या प्रथम जुलाई, 2017, जो भी बाद में हो, से लेकर परियोजना के पूरा होने या प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग, वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से पूर्व जिसमें समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया है या प्रथम अधिभोग निम्नानुसार अंतिम रूप से की जाएगी:

$$\text{टीए}^{\text{final}} = [\text{ई1} + \text{ई2} + \text{ई3}] / \text{एफ}] \times \text{टीए}^{\text{final}},$$

जहां,—

ई1 = अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त है

ई2 = अपार्टमेंट का कुल कार्पेट क्षेत्र, जिसका प्रदाय प्रथम अप्रैल, 2019 को कर की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आंशिक रूप से छूट और आंशिक रूप से कर योग्य है, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी, —

$$\text{ई2} = [\text{ऐसे अपार्टमेंट का कार्पेट क्षेत्र}] \times [\text{वी1} / (\text{वी1} + \text{वी2})] -$$

जहां,—

वी1, ऐसे अपार्टमेंट्स के प्रदाय का कुल मूल्य है जो कर से मुक्त था; तथा

वी2, ऐसे अपार्टमेंट्स के प्रदाय का कुल मूल्य है जो कर योग्य था

ई3 = अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र, जिसका निर्माण कर से मुक्त नहीं है, किंतु समापन प्रमाण-पत्र जारी करने या परियोजना के प्रथम अधिभोग जो भी पहले हो की तिथि तक बुक नहीं किया गया है.:

एफ = परियोजना में अपार्टमेंट्स का कुल कार्पेट क्षेत्र;

टीए<sup>final</sup> = परियोजना में प्रयुक्त सभी पूंजीगत मालों के संबंध में A<sup>final</sup> का कुल और प्रत्येक पूंजीगत मालों के लिए A<sup>final</sup> की गणना निम्नानुसार की जाएगी,

$$A^{\text{final}} = A \times (\text{मासों की संख्या जिनके लिए पूंजीगत मालों का उपयोग परियोजना के लिए किया जाता है} / 60)$$

तथा,—

(क) जहां टीए<sup>final</sup> का मूल्य, उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्धारित टीए की राशि से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष के अंत में, जिसमें समापन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या परियोजना का प्रथम अधिभोग होता है, आने वाले सितंबर मास के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में या प्ररूप डीआरसी -03 के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रिवर्सड की जाएगी और उक्त व्यक्ति भुगतान की तिथि तक अग्रिम वित्तीय वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर उक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा; या

(ख) जहां उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्धारित राशि का कुल टीए<sup>final</sup> से अधिक है, ऐसी अतिरिक्त राशि का दावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट के रूप में वित्तीय वर्ष के अंत में जिसमें समापन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या परियोजना पर प्रथम अधिभोग हो गया हो के आने वाले सितंबर मास के लिए उसकी विवरणी में किया जाएगा।

**व्याख्या।—** टीए<sup>final</sup> की गणना के प्रयोजन के लिए, मास का हिस्सा एक पूरे मास के रूप में माना जाएगा।

(3) केंद्रीय कर, राज्य कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए टीए<sup>final</sup> और टीए<sup>final</sup> की राशि की गणना अलग अलग की जाएगी।

(4) जहां किसी भी पूंजीगत माल का उपयोग एक से अधिक परियोजना के लिए किया जाता है, तो ऐसे पूंजीगत माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय प्रत्येक परियोजना को उचित आधार पर सौंपे जाएंगे और प्रत्येक परियोजना से संबंधित क्रेडिट रिवर्सल उप-नियम (2) के अनुसार किया जाएगा।

(5) जहां परियोजना के लिए उपयोग किए गए किसी भी पूंजीगत माल का उपयोग परियोजना के पूरा होने पर शेष रहता है, शेष जीवन के लिए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग, उस परियोजना, जिसमें पूंजीगत मालों का आगे भी उपयोग किया जाता है में किया जाएगा।";

- (iii) विद्यमान व्याख्या को "व्याख्या 1" के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इसके बाद इस प्रकार संख्यांकित की गई व्याख्या 1 के पश्चात्, निम्नलिखित व्याख्या रखी जायेगी, अर्थात्:—

**"व्याख्या 2:** नियम 42 और इस नियम के प्रयोजन के लिए, —

- (i) "अपार्टमेंट" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (ड.) में दिया गया है ;
- (ii) "परियोजना" शब्द का अर्थ होगा भू-सम्पदा परियोजना या आवासीय भू-सम्पदा परियोजना;
- (iii) "भू-सम्पदा परियोजना" का वही अर्थ होगा, जो इसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (यड) में दिया गया है;
- (iv) "आवासीय भू-सम्पदा परियोजना (आरआरईपी)" शब्द का अर्थ है, भू-सम्पदा परियोजना जिसमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कार्पेट क्षेत्र उस भू-सम्पदा परियोजना के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कार्पेट क्षेत्र के 15 प्रतिशत से अधिक न हो ;
- (v) "प्रोत्साहक" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (यट) में दिया गया है;
- (vi) "आवासीय अपार्टमेंट" से अभिप्राय होगा, भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकरण को यथा घोषित आवासीय उपयोग के लिए आशयित कोई अपार्टमेंट;
- (vii) "वाणिज्यिक अपार्टमेंट" का अभिप्राय होगा, आवासीय अपार्टमेंट से भिन्न कोई अपार्टमेंट ;
- (viii) "आवासीय अपार्टमेंट" की परिभाषा में यथा वर्णित "सक्षम प्राधिकरण", से अभिप्राय है केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा तत्समय लागू किसी विधि के अधीन सृजित या स्थापित स्थानीय प्राधिकरण या अन्य कोई प्राधिकरण जो अपनी अधिकारिता में ऐसे भू-खण्ड पर प्राधिकार रखता हो और जिसको ऐसी अचल संपत्ति के विकास के लिए अनुमति देने की शक्ति प्राप्त हो;
- (ix) "भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण" शब्द का अर्थ है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 20 (1) के अधीन स्थापित प्राधिकरण;
- (x) "कार्पेट क्षेत्र" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (ट) में दिया गया हो ;
- (xi) "समापन प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि को या से पूर्व या परियोजना के प्रथम अधिभोग पर बुक किया गया कोई अपार्टमेंट" से अभिप्राय होगा कोई अपार्टमेंट जो निम्नलिखित सभी तीन शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात्:—
  - (क) अपार्टमेंट सेवा के निर्माण के प्रदाय का भाग उक्त तिथि को या से पूर्व प्रदाय का समय है; तथा
  - (ख) उक्त तिथि को या से पूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के बैंक खाते में कम से कम एक किस्त के बराबर का प्रतिफल जमा करवा दिया गया हो;
  - (ग) उक्त तिथि को अथवा से पूर्व कोई आवंटन पत्र या विक्रय करार या अपार्टमेंट की बुकिंग जारी कर दी गई है के साक्ष्य वाला कोई अन्य समान दस्तावेज।
- (xii) "चालू परियोजना" का वही अर्थ होगा, जो इसे हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में दिया गया हो।
- (xiii) "प्रथम अप्रैल, 2019 को या के बाद शुरू होने वाली परियोजना" शब्दों का वही अर्थ होगा जो इसे हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में दिया गया हो।"

5. उक्त नियमों में, नियम 88 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा और 29 मार्च, 2019 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

**"नियम 88क. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम—**एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का प्रथमतः उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसका उपयोग, केंद्रीय कर और राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, के भुगतान के लिए किसी क्रम में किया जा सकता है:

परंतु केंद्रीय कर और राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर का भुगतान, जैसी भी स्थिति हो, केवल एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का प्रथमतः पूर्णतया उपयोग किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।"

6. उक्त नियमों में, नियम 100 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"100. कतिपय मामलों में निर्धारण—(1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-13 में जारी किया जाएगा और उसका सारांश प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया जाएगा ।

(2) समुचित अधिकारी कराधेय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14 में धारा 63 के उपबंधों के अनुसार नोटिस जारी करेगा, जिसमें वह आधार अंतर्विष्ट होंगे जिनके आधार पर सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है तथा उसके सारांश की तामील इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में भी की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए पंद्रह दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात्, प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-15 में आदेश पारित करेगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में अपलोड किया जाएगा ।

(3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-16 में जारी किया जाएगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में अपलोड किया जाएगा ।

(4) धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण करने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-17 में आवेदन कर सकता है ।

(5) यथास्थिति, प्रतिसंहरण आदेश या धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार करने का आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-18 में जारी किया जाएगा ।"

7. उक्त नियमों में, नियम 142 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"142. अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य राशियों की मांग के लिए नोटिस और आदेश—(1) समुचित अधिकारी निम्नलिखित के साथ,—

(क) धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी नोटिस के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में उसके सारांश की प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में तामील करेगा,

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन विवरण, उसका सारांश इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 भुगतानयोग्य राशि के ब्यौरों को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ।

(2) जहां नोटिस या विवरण की तामील से पूर्व, कर से प्रभार्य व्यक्ति, धारा 73 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार कर और ब्याज का भुगतान करता है या जैसी भी स्थिति हो, धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज तथा शास्ति का भुगतान कर देता है या जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोध्य राशि का भुगतान कर देता है तो वह समुचित अधिकारी को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे भुगतान की सूचना देगा और समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान की अभिस्वीकृति, स्वकृति जारी करेगा ।

(3) जहां कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन, कर और ब्याज का भुगतान करता है या जैसी भी स्थिति हो, उपनियम (1) के अधीन नोटिस की तामील के तीस दिन के भीतर धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति का भुगतान करता है या जहां संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि का माल और प्रवहन को निरुद्ध करने या जब्त करने के चौदह दिन के भीतर भुगतान करता है तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे भुगतान की समुचित अधिकारी को संसूचना देगा तथा समुचित अधिकारी उक्त नोटिस के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश जारी करेगा ।

(4) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन या किसी धारा के अधीन जारी किसी नोटिस का प्रत्युत्तर, जिसका सारांश उपनियम (1) के अधीन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया गया है, को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06 में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) धारा 52 या धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 75 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन जारी किए गए आदेश के सारांश को उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य कर, ब्याज और शास्ति की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जाएगा ।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश वसूली के लिए आदेश के रूप में माना जाएगा ।

(7) जहां आदेश का परिशोधन धारा 161 के उपबंधों के अनुसार पारित किया गया है या सिस्टम में अपलोड किया गया कोई आदेश प्रतिसंहरण कर लिया गया है, परिशोधन आदेश या प्रतिसंहरण आदेश का सारांश प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 में समुचित अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से अपलोड किया जाएगा ।"

8. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

<b>"प्ररूप जीएसटी डीआरसी- 01</b> <b>[देखिये नियम 100 (2) और नियम 142(1)(क)]</b> <b>तिथि:</b>											
संदर्भ संख्या :											
सेवा में,											
_____ जीएसटीआईएन/अस्थाई पहचान											
_____ नाम											
_____ पता											
कर अवधि -----				वि.व. -----				अधिनियम --			
धारा / उपधारा जिसके अधीन एससीएन जारी किया गया --											
एससीएन संदर्भ संख्या -----						तिथि -----					
कारण बताओ सूचना का सारांश											
(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य :											
(ख) आधार											
(ग) कर और अन्य देय :											
(राशि रुपए में)											
क्रम संख्या	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	(प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											
हस्ताक्षर नाम पदनाम अधिकारिता पता											
टिप्पण --											
1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।											
2. उपरोक्त सारणी के खाना संख्या 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।											
3. प्रदाय का स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है ।"											

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

<b>प्ररूप जीएसटी डीआरसी -02</b> [देखिये नियम 142(1)(ख)]											
संदर्भ संख्या:						तिथि:					
सेवा में,											
_____ जीएसटीआईएन/पहचान											
_____ नाम											
_____ पता											
कर अवधि :						वि.व. :					
धारा /उपधारा जिसके अधीन विवरण जारी किया गया :											
एससीएन संदर्भ संख्या -----						तिथि -					
विवरण संदर्भ संख्या -----						तिथि -					
विवरण का सारांश :											
(क) मामले के संक्षिप्त तथ्य :											
(ख) आधार :											
(ग) कर और अन्य देय :-											
(राशि रुपए में)											
क्रम संख्या	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	(प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											
हस्ताक्षर नाम पदनाम अधिकारिता पता											
टिप्पण -											
(1) केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।											
(2) उपरोक्त सारणी के खाना संख्या 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।											
(3) प्रदाय के स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन की गई है ।" ।											

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

<b>“प्ररूप जीएसटी डीआरसी -07</b> <b>[देखिये नियम 100(1), 100(2), 100(3) और 142(5)]</b>																				
संदर्भ संख्या:						तिथि:														
1. आदेश के ब्यौरे : (क) आदेश संख्या (ख) आदेश की तिथि (ग) वित्तीय वर्ष (घ) कर अवधि .....से .....तक																				
2. अंतर्वलित निर्गमन																				
3. माल/सेवाओं का विवरण (यदि लागू हों)																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>एचएसएन कोड</th> <th>विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>												क्रम संख्या	एचएसएन कोड	विवरण						
क्रम संख्या	एचएसएन कोड	विवरण																		
4. अधिनियम की धारा (धाराएं) जिसके अधीन मांग सृजित की गई है :																				
5. मांग के ब्यौरे :																				
(राशि रुपए में)																				
क्रम संख्या	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	(प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग									
			से	तक																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
योग																				

आपको <तिथि> तक भुगतान करने का निदेश दिया जाता है, जिसके असफल होने पर आपके विरुद्ध बकाया देय की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

हस्ताक्षर  
 नाम  
 पदनाम  
 अधिकारिता  
 पता

सेवा में,

.....(जीएसटीआईएन/पहचान)

.....नाम

..... (पता)

टिप्पण -

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।

2. उपरोक्त सारणी के खाना संख्या 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।

3. प्रदाय के स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।” ।

11. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-08 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

<b>"प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 08</b> <b>[देखिये नियम 142(7)]</b>																																																													
संदर्भ संख्या:						तिथि:																																																							
परिशोधन/प्रतिसंहरण आदेश का सारांश																																																													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 1. आदेश की विशिष्टियाँ: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">(क) वित्तीय वर्ष, यदि लागू हो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(ख) कर अवधि, यदि कोई हो</td> <td>से ----- तक -----</td> </tr> <tr> <td>(ग) धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(घ) मूल आदेश संख्या</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(ङ) मूल आदेश की तिथि</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(च) परिशोधन आदेश संख्या</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(छ) परिशोधन आदेश की तिथि</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(ज) एआरएन, यदि परिशोधन के लिए लागू हो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(झ) एआरएन की तिथि</td> <td></td> </tr> </table> </div>												(क) वित्तीय वर्ष, यदि लागू हो		(ख) कर अवधि, यदि कोई हो	से ----- तक -----	(ग) धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है		(घ) मूल आदेश संख्या		(ङ) मूल आदेश की तिथि		(च) परिशोधन आदेश संख्या		(छ) परिशोधन आदेश की तिथि		(ज) एआरएन, यदि परिशोधन के लिए लागू हो		(झ) एआरएन की तिथि																																	
(क) वित्तीय वर्ष, यदि लागू हो																																																													
(ख) कर अवधि, यदि कोई हो	से ----- तक -----																																																												
(ग) धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है																																																													
(घ) मूल आदेश संख्या																																																													
(ङ) मूल आदेश की तिथि																																																													
(च) परिशोधन आदेश संख्या																																																													
(छ) परिशोधन आदेश की तिथि																																																													
(ज) एआरएन, यदि परिशोधन के लिए लागू हो																																																													
(झ) एआरएन की तिथि																																																													
2. ऊपर निर्दिष्ट आदेश के परिशोधन के लिए आपके आवेदन की जांच की गई <input type="checkbox"/>																																																													
3. यह मेरे संज्ञान में आया है कि ऊपरोक्त आदेश में परिशोधन अपेक्षित है (संलग्न उपाबंध के अनुसार परिशोधन के कारण) <input type="checkbox"/>																																																													
4. ऊपर निर्दिष्ट आदेश (धारा 129 के अधीन जारी) को वापस लिए जाने की अपेक्षा <input type="checkbox"/>																																																													
5. माल / सेवाओं का विवरण (यदि लागू हो) : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">क्रम संख्या</th> <th style="width: 20%;">एचएसएन कोड</th> <th style="width: 65%;">विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>												क्रम संख्या	एचएसएन कोड	विवरण																																															
क्रम संख्या	एचएसएन कोड	विवरण																																																											
6. अधिनियम की धारा जिसके अधीन मांग का सृजन किया गया है:																																																													
7. परिशोधन के पश्चात् मांग के ब्यौरे, यदि कोई हों: <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">(राशि रुपए में)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्रम संख्या</th> <th rowspan="2">कर दर</th> <th rowspan="2">आवर्त</th> <th colspan="2">कर अवधि</th> <th rowspan="2">अधिनियम</th> <th rowspan="2">(प्रदाय का स्थान)</th> <th rowspan="2">कर</th> <th rowspan="2">ब्याज</th> <th rowspan="2">शास्ति</th> <th rowspan="2">अन्य</th> <th rowspan="2">योग</th> </tr> <tr> <th>से</th> <th>तक</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>												क्रम संख्या	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	(प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग	से	तक	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													योग											
क्रम संख्या	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	(प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग																																																		
			से	तक																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																		
योग																																																													
आपको <तिथि> तक भुगतान करने का निदेश दिया जाता है, जिसके असफल होने पर आपके विरुद्ध बकाया देय की वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी । <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> हस्ताक्षर  नाम  पदनाम  अधिकारिता  पता </div>																																																													

सेवा में,

.....(जीएसटीआईएन/पहचान)

.....नाम

..... (पता)

टिप्पण –

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
2. उपरोक्त सारणी के खाना संख्या 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
3. प्रदाय के स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।
4. क्रम संख्या 7 पर की मांग सारणी को नहीं भरा जाएगा, यदि धारा 129 के अधीन जारी आदेश वापस ले लिया गया है ।” ।

12. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एसएमटी –13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"प्ररूप जीएसटी एसएमटी – 13**

[देखिये नियम 100(1)]

संदर्भ संख्या :

तिथि:

सेवा में

\_\_\_\_\_ (जीएसटीआईएन/पहचान)

\_\_\_\_\_ नाम

\_\_\_\_\_ (पता)

कर अवधि :

वि.व. :

विवरणी का प्रकार :

सूचना संदर्भ संख्या:

तिथि :

अधिनियम/नियमों के उपबंध:

(धारा 62 के अधीन निर्धारण)

उद्देशिका – << मानक >>

पूर्वोक्त निर्दिष्ट नोटिस को आपको अधिनियम की धारा 46 के अधीन उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए जारी किया गया था। विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों से यह पाया गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

इसलिए, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, निर्धारित राशि और आपके द्वारा भुगतान योग्य राशि नीचे दिए गए अनुसार है :

प्रस्तावना :

दलील, यदि कोई हो :

चर्चा और निष्कर्ष :

निर्णय :

निर्धारित और भुगतान योग्य राशि (ब्यौरे उपाबंध पर) :

(राशि रुपए में)

क्रम संख्या	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	(प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तिथि तक की गई है। भुगतान करते समय, आदेश करने की तिथि और भुगतान करने की तिथि के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की जाएगी और आदेश में कथित शोध्यों के साथ भुगतान की जाएगी।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप इस आदेश के तामील की तिथि से तीस दिन के अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करते हैं तो इस आदेश को प्रतिसंहत किया गया समझा जाएगा; अन्यथा पूर्वोक्त अवधि के पश्चात् बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण –

- केवल लागू स्थानों को भरा जाए।
- उपरोक्त सारणी के खाना संख्या 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है।
- प्रदाय के स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है।

13. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एसएमटी – 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**\*जीएसटी एसएमटी – 15**

[देखिये नियम 100(2)]

संदर्भ संख्या :  
सेवा में,

तिथि:

\_\_\_\_ (जीएसटीआई/आईडी)  
\_\_\_\_ नाम  
\_\_\_\_ (पता )

कर अवधि :  
एससीएन संदर्भ संख्या :

वित्त वर्ष :

तिथि :

अधिनियम/नियमों के उपबंध:

(धारा 63 के अधीन निर्धारण)

उद्देशिका – << मानक >>

पूर्वोक्त निर्दिष्ट नोटिस आपको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने के बावजूद एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रूप में कारबार का संचालन जारी रखने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी ।

या

पूर्वोक्त निर्दिष्ट नोटिस आपको उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी कि आपको ..... अवधि के लिए क्यों न कर का भुगतान करना चाहिए, चूंकि आपके रजिस्ट्रीकरण को ..... तिथि से धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है । और आपके द्वारा कोई उत्तर दायर नहीं किया गया है या .... तिथि को आयोजित कार्यवाहियों के दौरान आपके प्रत्युत्तर पर सम्यक् विचार किया गया है ।

विभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर, कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निर्धारित और आपके द्वारा भुगतान योग्य राशि नीचे दिए अनुसार है :

प्रस्तावना :

दलील, यदि कोई हो :

निष्कर्ष (कार्यवाहियों को समाप्त करने या मांग सृजित करने के लिए) :

निर्धारित और भुगतान योग्य राशि :

(राशि रूप में)

क्रम संख्या	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	(प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शारित	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तिथि तक की गई है। भुगतान करते समय आदेश करने की तिथि और भुगतान करने की तिथि के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की जाएगी और आदेश में कथित शोध्यों के साथ भुगतान किया जाएगा ।

आपको निदेश दिया जाता है कि तिथि .... तक भुगतान करें, जिसके न किए जाने पर बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी ।

हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम  
अधिकारिता  
पता

टिप्पण –

- केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।
- उपरोक्त सारणी के खाना संख्या 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।
- प्रदाय के स्थान (पीओएस) के ब्योरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।”।

## 14. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एसएमटी – 16 के स्थान पर, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## "जीएसटी एसएमटी – 16

[देखिये नियम 100(3)]

संदर्भ संख्या:

तिथि:

सेवा में

\_\_\_\_\_ (जीएसटीआईडीआईडी)

\_\_\_\_\_ नाम

\_\_\_\_\_ (पता )

कर अवधि :

वित्त वर्ष :

अधिनियम/नियमों के उपबंध:

(धारा 64 के अधीन निर्धारण)

प्रस्तावना – &lt;&lt; मानक &gt;&gt;

मेरे नोटिस में यह आया है कि ..... गोदाम (पता) में या .... में (पता और यान का ब्यौरा) खड़े किए हुए यान में ऐसे माल पड़े हैं, जिनको कोई लेखा-जोखा नहीं है और आप इन मालों का लेखा देने या मालों के ब्यौरे को उपदर्शित करने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए थे । अतः, ऐसे मालों पर नीचे दिए अनुसार कर का निर्धारण करने के लिए मैं अग्रसर होता हूँ ।

प्रस्तावना :

चर्चा और निष्कर्ष :

निर्णय :

निर्धारित और भुगतान योग्य राशि (ब्यौरे उपाबंध पर) :

(राशि रुपए में)

क्रम संख्या	कर दर	आवर्त	कर अवधि		अधिनियम	(प्रदाय का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
			से	तक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योग											

कृपया नोट करें कि ब्याज की संगणना आदेश पारित करने की तिथि तक की गई है । भुगतान करते समय आदेश करने की तिथि और भुगतान करने की तिथि के बीच की अवधि के लिए ब्याज की गणना भी की जाएगी और आदेश में कथित शोध्यों के साथ भुगतान योग्य किया जाएगा ।

आपको निदेश दिया जाता है कि तिथि .... तक भुगतान करें, जिसके न किए जाने पर बकाया शोध्यों की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

पता

टिप्पण –

1. केवल लागू स्थानों को भरा जाए ।

2. उपरोक्त सारणी के खाना संख्या 2, 3, 4 और 5 अर्थात् कर दर, आवर्त और कर अवधि आज्ञापक नहीं है ।

3. प्रदाय के स्थान (पीओएस) के ब्यौरे केवल तभी अपेक्षित होंगे यदि मांग आईजीएसटी अधिनियम के अधीन सृजित की गई है ।” ।

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी सीपीडी – 02 में सारणी और सारणी के नीचे टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी और टिप्पण प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

क्रम संख्या	अपराध	अधिनियम	प्रशमनीय राशि(रूपये)
(1)	(3)	(3)	(4)

टिप्पण: (1) यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध खाना (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणियों में आता है, तो प्रशमनीय राशि वह राशि होगी, जो खाना (3) में विनिर्दिष्ट है, जो उन श्रेणियों के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि होगी, जिनमें प्रशमनीय किए जाने वाले अपराध को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है ।

(2) इस राशि को लघु शीर्ष "अन्य" में जमा किया जाएगा । " ।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 11th April, 2019

**No. 54/GST-2.**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following Rules to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2019.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into effect from 1st April, 2019.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 41, in sub-rule (1), after the proviso, the following explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 29th March, 2019, namely: -

**“Explanation.**- For the purpose of this sub-rule, it is hereby clarified that the “value of assets” means the value of the entire assets of the business, whether or not input tax credit has been availed thereon.”.

3. in the said rules, in rule 42,-

(a) in sub rule (1),-

- a. in clause (f), the following Explanation shall be inserted, namely:-

**“Explanation.** For the purpose of this clause, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the said Act, value of T4 shall be zero during the construction phase because inputs and input services shall be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date.”;

- b. in clause (g), after the letter and figure “**FORM GSTR-2**”, the words, letters and figure “**and at summary level in FORM GSTR-3B**” shall be inserted;
- c. in clause (h), for the brackets and letter “(g)”, the brackets and letter “(f)” shall be substituted;
- d. in clause (i),-
  - i. before the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the value of “E/F” for a tax period shall be calculated for each project separately, taking value of E and F as under:-

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but are identified by the promoter to be sold after issue of completion certificate or first occupation, whichever is earlier;

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

**Explanation 1:** In the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartments, which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier;

**Explanation 2:** Carpet area of apartments, tax on construction of which is paid or payable at the rates specified for items (i), (ia), (ib), (ic) or (id), against serial number 3 of the Table in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended, shall be taken into account for calculation of value of “E” in view of Explanation (iv) in paragraph 4 of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended.

- ii. in the existing proviso, for the word “Provided”, the words “Provided further” shall be substituted;
- e. for clause (l), the following clause shall be substituted, namely:-  
 “(l) the amount “C3”, “D1” and “D2” shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax and integrated tax and declared in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03**”;
- f. in clause (m), for the words “added to the output tax liability of the registered person”, the words, letters and figures “reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03**” shall be substituted;
- (b) in sub-rule (2), for the words “The input tax credit”, the words, figures and bracket “Except in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the input tax credit” shall be substituted;
- (c) in clause (a) of sub-rule (2), for the words “added to the output tax liability of the registered person”, the words, letters and figures “reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03**” shall be substituted;
- (d) after sub-rule (2), the following sub rules shall be inserted, namely:-  
 “(3) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the input tax determined under sub-rule (1) shall be calculated finally, for each ongoing project or project which commences on or after 1st April, 2019, which did not undergo or did not require transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019 in accordance with the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, in the manner prescribed in the said sub-rule, with the modification that value of E/F shall be calculated taking value of E and F as under:

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier;

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

and,-

(a) where the aggregate of the amounts calculated finally in respect of “D1” and “D2” exceeds the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of “D1” and “D2”, such excess shall be reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation of the project takes place and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or

(b) where the aggregate of the amounts determined under sub-rule (1) in respect of “D1” and “D2” exceeds the aggregate of the amounts calculated finally in respect of “D1” and “D2”, such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

(4) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the input tax determined under sub-rule (1) shall be calculated finally, for commercial portion in each project, other than residential real estate project (RREP), which underwent transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on the 1st April, 2019 in accordance with the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, in the following manner.

(a) The aggregate amount of common credit on commercial portion in the project ( $C3_{\text{aggregate\_comm}}$ ) shall be calculated as under,

$$C3_{\text{aggregate\_comm}} = [\text{aggregate of amounts of } C3 \text{ determined under sub- rule (1) for the tax periods starting from 1st July, 2017 to 31st March, 2019, } \times (A_C / A_T)] + [\text{aggregate of amounts of } C3 \text{ determined under sub- rule (1) for the tax periods starting from 1st April, 2019 to the date of completion or first occupation of the project, whichever is earlier}]$$

Where, -

$A_C$  = total carpet area of the commercial apartments in the project

$A_T$  = total carpet area of all apartments in the project

(b) The amount of final eligible common credit on commercial portion in the project ( $C3_{\text{final\_comm}}$ ) shall be calculated as under

$$C3_{\text{final\_comm}} = C3_{\text{aggregate\_comm}} \times (E / F)$$

Where, -

$E$  = total carpet area of commercial apartments which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier.

$F = A_C$  = total carpet area of the commercial apartments in the project

(c) where,  $C3_{\text{aggregate\_comm}}$  exceeds  $C3_{\text{final\_comm}}$ , such excess shall be reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in sub-section (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment;

(d) where,  $C3_{\text{final\_comm}}$  exceeds  $C3_{\text{aggregate\_comm}}$ , such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

(5) Input tax determined under sub- rule (1) shall not be required to be calculated finally on completion or first occupation of an RREP which underwent transition of input tax credit consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019 in accordance with the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended.

(6) Where any input or input service are used for more than one project, input tax credit with respect to such input or input service shall be assigned to each project on a reasonable basis and credit reversal pertaining to each project shall be carried out as per sub-rule (3).”.

4. In the said rules, in rule 43,-

(i) in sub rule (1),-

(a) in clause (a), after the words, letters and figures “**FORM GSTR-2**”, the words, letters and figure “and **FORM GSTR-3B**” shall be inserted;

(b) in clause (b),-

i. after the letters and figure “**FORM GSTR-2**”, the words, letters and figures “and **FORM GSTR-3B**” shall be inserted;

ii. in the end, the following explanation shall be inserted, namely: -

**“Explanation:** For the purpose of this clause, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the said Act, the amount of input tax in respect of capital goods used or intended to be used exclusively for effecting supplies other than exempted supplies but including zero rated supplies, shall be zero during the construction phase because capital goods will be commonly used for construction of apartments booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier, and those which are not booked by the said date.”;

(c) in clause (g),-

(A) after the letter and words “ ‘F’ is the total turnover”, the words “in the State” shall be inserted;

(B) Before the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of the Schedule II of the Act, the value of “E/F” for a tax period shall be calculated for each project separately, taking value of E and F as under:

E= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax plus aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but are identified by the promoter to be sold after issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier;

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

**Explanation1:** In the tax period in which the issuance of completion certificate or first occupation of the project takes place, value of E shall also include aggregate carpet area of the apartments, which have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier.

**Explanation 2:** Carpet area of apartments, tax on construction of which is paid or payable at the rates specified for items (i), (ia), (ib), (ic) or (id), against serial number 3 of the Table in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended, shall be taken into account for calculation of value of ‘E’ in view of Explanation (iv) in paragraph 4 of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended.”;

(C) in the existing proviso, for the word “Provided”, the words “Provided further” shall be substituted;

(d) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely,-

“(i) The amount  $T_e$  shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax and integrated tax and declared in **FORM GSTR-3B**.”;

(ii) for sub rule (2), the following sub rules shall be substituted, namely:-

“(2) In case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the Act, the amount of common credit attributable towards exempted supplies ( $T_{\text{final}}$ ) shall be calculated finally for the entire period from the commencement of the project or 1st July, 2017, whichever is later, to the completion or first occupation of the project, whichever is earlier, for each project separately, before the due date for furnishing of the return for the month of September following the end of financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project, as under:

$$T_{\text{final}} = [(E1 + E2 + E3) / F] \times T_{\text{final}}$$

Where,-

E1= aggregate carpet area of the apartments, construction of which is exempt from tax

E2= aggregate carpet area of the apartments, supply of which is partly exempt and partly taxable, consequent to change of rates of tax on 1st April, 2019, which shall be calculated as under, -

$$E2 = [\text{Carpet area of such apartments}] \times [V_1 / (V_1 + V_2)], -$$

Where,-

$V_1$  is the total value of supply of such apartments which was exempt from tax; and

$V_2$  is the total value of supply of such apartments which was taxable

E3 = aggregate carpet area of the apartments, construction of which is not exempt from tax, but have not been booked till the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project, whichever is earlier:

F= aggregate carpet area of the apartments in the project;

$T_{\text{final}}$  = aggregate of  $A_{\text{final}}$  in respect of all capital goods used in the project and  $A_{\text{final}}$  for each capital goods shall be calculated as under,

$A_{\text{final}} = A \times (\text{number of months for which capital goods is used for the project} / 60)$  and,-

(a) where value of  $T_{\text{final}}$  exceeds the aggregate of amounts of  $T_{\text{e}}$  determined for each tax period under sub-rule (1), such excess shall be reversed by the registered person in **FORM GSTR-3B** or through **FORM GST DRC-03** in the month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project and the said person shall be liable to pay interest on the said excess amount at the rate specified in subsection (1) of section 50 for the period starting from the first day of April of the succeeding financial year till the date of payment; or

(b) where aggregate of amounts of  $T_{\text{e}}$  determined for each tax period under sub-rule (1) exceeds  $T_{\text{final}}$ , such excess amount shall be claimed as credit by the registered person in his return for a month not later than the month of September following the end of the financial year in which the completion certificate is issued or first occupation takes place of the project.

*Explanation 1.*- For the purpose of calculation of  $T_{\text{final}}$ , part of the month shall be treated as one complete month.

(3) The amount  $T_{\text{final}}$  and  $T_{\text{final}}$  shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax and integrated tax.

(4) Where any capital goods are used for more than one project, input tax credit with respect to such capital goods shall be assigned to each project on a reasonable basis and credit reversal pertaining to each project shall be carried out as per sub-rule (2).

(5) Where any capital goods used for the project have their useful life remaining on the completion of the project, input tax credit attributable to the remaining life shall be availed in the project in which the capital goods is further used;”;

(iii) the Explanation shall be numbered as “*Explanation 1*” thereof and after *Explanation 1* as so numbered the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

“*Explanation 2:* For the purposes of rule 42 and this rule,-

- (i) the term “apartment” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);
- (ii) the term “project” shall mean a real estate project or a residential real estate project;
- (iii) the term “Real Estate Project (REP)” shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);
- (iv) the term “Residential Real Estate Project (RREP)” shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent of the total carpet area of all the apartments in the REP;
- (v) the term “promoter” shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);
- (vi) “Residential apartment” shall mean an apartment intended for residential use as declared to the Real Estate Regulatory Authority or to competent authority;
- (vii) “Commercial apartment” shall mean an apartment other than a residential apartment;
- (viii) the term “competent authority” as mentioned in definition of “residential apartment”, means the local authority or any authority created or established under any law for the time being in force by the Central Government or State Government or Union Territory Government, which exercises authority over land under its jurisdiction, and has powers to give permission for development of such immovable property;
- (ix) the term “Real Estate Regulatory Authority” shall mean the Authority established under sub-section (1) of section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016) by the Central Government or State Government;
- (x) the term “carpet area” shall have the same meaning assigned to it in clause (k) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);
- (xi) “an apartment booked on or before the date of issuance of completion certificate or first occupation of the project” shall mean an apartment which meets all the following three conditions, namely-
  - (a) part of supply of construction of the apartment service has time of supply on or before the said date; and
  - (b) consideration equal to at least one installment has been credited to the bank account of the registered person on or before the said date; and
  - (c) an allotment letter or sale agreement or any other similar document evidencing booking of the apartment has been issued on or before the said date.
- (xii) The term “ongoing project” shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended;
- (xiii) The term “project which commences on or after 1st April, 2019” shall have the same meaning as assigned to it in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017, as amended;”.

5. In the said rules, after rule 88, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 29th March, 2019, namely: -

**“Rule 88A. Order of utilization of input tax credit.-** Input tax credit on account of integrated tax shall first be utilised towards payment of integrated tax, and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of central tax and State tax, as the case may be, in any order:

Provided that the input tax credit on account of central tax, State tax shall be utilised towards payment of integrated tax, central tax, State tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully.”.

6. In the said rules, for rule 100, the following rule shall be substituted, namely:—

“**100. Assessment in certain cases.**— (1) The order of assessment made under sub-section (1) of section 62 shall be issued in **FORM GST ASMT-13** and a summary thereof shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**.

(2) The proper officer shall issue a notice to a taxable person in accordance with the provisions of section 63 in **FORM GST ASMT-14** containing the grounds on which the assessment is proposed to be made on best judgment basis and shall also serve a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**, and after allowing a time of fifteen days to such person to furnish his reply, if any, pass an order in **FORM GST ASMT-15** and summary thereof shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**.

(3) The order of assessment under sub-section (1) of section 64 shall be issued in **FORM GST ASMT-16** and a summary of the order shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**.

(4) The person referred to in sub-section (2) of section 64 may file an application for withdrawal of the assessment order in **FORM GST ASMT-17**.

(5) The order of withdrawal or, as the case may be, rejection of the application under sub-section (2) of section 64 shall be issued in **FORM GST ASMT-18**.”

7. In the said rules, for rule 142, the following rule shall be substituted, namely:—

“**142. Notice and order for demand of amounts payable under the Act.**— (1) The proper officer shall serve, along with the

- (a) notice issued under section 52 or section 73 or section 74 or section 76 or section 122 or section 123 or section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**,
- (b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-02**, specifying therein the details of the amount payable.

(2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74, or where any person makes payment of tax, interest, penalty or any other amount due in accordance with the provisions of the Act he shall inform the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in **FORM GST DRC-04**.

(3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under subsection (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), or where the person concerned makes payment of the amount referred to in sub-section (1) of section 129 within fourteen days of detention or seizure of the goods and conveyance, he shall intimate the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an order in **FORM GST DRC-05** concluding the proceedings in respect of the said notice.

(4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 or the reply to any notice issued under any section whose summary has been uploaded electronically in **FORM GST DRC-01** under sub-rule (1) shall be furnished in **FORM GST DRC-06**.

(5) A summary of the order issued under section 52 or section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 75 or section 76 or section 122 or section 123 or section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130 shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**, specifying therein the amount of tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax.

(6) The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.

(7) Where a rectification of the order has been passed in accordance with the provisions of section 161 or where an order uploaded on the system has been withdrawn, a summary of the rectification order or of the withdrawal order shall be uploaded electronically by the proper officer in **FORM GST DRC-08**.”

8. In the said rules, for **FORM GST DRC-01**, the following FORM shall be substituted, namely:—

<b>“FORM GST DRC - 01</b> <i>[See rule 100 (2) &amp; 142(1)(a)]</i>											
Reference No:						Date:					
To _____ GSTIN/Temp. ID ----- Name _____ Address											
Tax Period -----						F.Y. -----			Act -		
Section / sub-section under which SCN is being issued - SCN Reference No. ---- Date ----											
<b>Summary of Show Cause Notice</b>											
Brief facts of the case :											
Grounds :											
Tax and other dues :											
(Amount in Rs.)											
Serial Number	Tax rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
			From	To							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											
Signature Name Designation Jurisdiction Address											
<b>Note -</b> 1. Only applicable fields may be filled up. 2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory. 3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.”.											

9. In the said rules, for **FORM GST DRC-02**, the following FORM shall be substituted, namely:—

**“FORM GST DRC -02**

*[See rule 142(1)(b)]*

Reference No:

Date:

To

\_\_\_\_\_ GSTIN/ID

----- Name

\_\_\_\_\_ Address

Tax Period :

F.Y. :

Section /sub-section under which statement is being issued :

SCN Ref. No. -----

Date –

Statement Ref. No. ----

Date –

**Summary of Statement :**

(a) Brief facts of the case :

(b) Grounds :

(c) Tax and other dues :

(Amount in Rs.)

Serial Number	Tax rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
			From	To							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											

Signature  
Name  
Designation  
Jurisdiction  
Address

**Note -**

- Only applicable fields may be filled up.
- Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.
- Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.”.

10. In the said rules, for **FORM GST DRC-07**, the following FORM shall be substituted, namely:—

<b>“FORM GST DRC-07</b> <i>[See rule 100(1), 100(2), 100(3) &amp; 142(5)]</i> <b>Summary of the order</b>																				
Reference No. -						Date –														
1. Details of order :																				
(a) Order No. :																				
(b) Order date :																				
(c) Financial year:																				
(d) Tax period: From --- To -----																				
2. Issues involved :																				
3. Description of goods / services (if applicable):																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Sr. No.</th> <th style="width: 20%;">HSN code</th> <th style="width: 65%;">Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>												Sr. No.	HSN code	Description						
Sr. No.	HSN code	Description																		
4. Section(s) of the Act under which demand is created:																				
5. Details of demand :																				
(Amount in Rs.)																				
Serial Number	Tax Rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Others	Total									
			From	To																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Total																				
<p>You are hereby directed to make the payment by &lt;Date&gt; failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.</p>																				
Signature Name Designation Jurisdiction Address																				
To _____ (GSTIN/ID)																				
-----Name _____ (Address )																				
<b>Note –</b>																				
1. Only applicable fields may be filled up.																				
2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the Table at serial no. 5 i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.																				
3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.”.																				

11. In the said rules, for **FORM GST DRC-08**, the following FORM shall be substituted, namely:—

**“FORM GST DRC - 08**

*[See rule 142(7)]*

Reference No.:

Date:

**Summary of Rectification /Withdrawal Order**

1. Particulars of order:	
(a) Financial year, if applicable	
(b) Tax period, if any	From --- To ----
(c) Section under which order is passed	
(d) Original order no.	
(e) Original order date	
(f) Rectification order no.	
(g) Rectification order date	
ARN, if applied for rectification	
(i) Date of ARN	

2. Your application for rectification of the order referred to above has been examined ☐
3. It has come to my notice that the above said order requires rectification (Reason for rectification as per attached annexure) ☐
4. The order referred to above (issued under section 129) requires to be withdrawn ☐
5. Description of goods / services (if applicable) :

Serial Number	HSN code	Description

6. Section of the Act under which demand is created:

7. Details of demand, if any, after rectification :

(Amount in Rs.)

Serial Number	Tax Rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
			From	To							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											

You are hereby directed to make the payment by <Date> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.

Signature  
Name  
Designation  
Jurisdiction  
Address

To

\_\_\_\_\_ (GSTIN/ID)

\_\_\_\_\_ Name

\_\_\_\_\_ (Address )

**Note –**

1. Only applicable fields may be filled up.
2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the Table at serial no. 7 i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.
3. Place of Supply (POS) details shall be required only if the demand is created under the IGST Act.
4. Demand table at serial no. 7 shall not be filled up if an order issued under section 129 is being withdrawn.”.

12. In the said rules, for **FORM GST ASMT-13**, the following FORM shall be substituted, namely:-

<b>“FORM GST ASMT- 13</b> <i>[See rule 100(1)]</i>											
Reference No.:						Date:					
To											
_____ (GSTIN/ID)											
_____ Name											
_____ (Address )											
Tax Period :				F.Y. :				Return Type :			
Notice Reference No.:								Date :			
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;"><b>Act/ Rules Provisions:</b></div>											
<b>(Assessment order under Section 62)</b>											
Preamble - << standard >>											
The notice referred to above was issued to you under section 46 of the Act for failure to furnish the return for the said tax period. From the records available with the department, it has been noticed that you have not furnished the said return till date.											
Therefore, on the basis of information available with the department, the amount assessed and payable by you is as under:											
Introduction :											
Submissions, if any :											
Discussions and Findings :											
Conclusion :											
Amount assessed and payable (Details at Annexure):											
(Amount in Rs.)											
Serial Number	Tax rate	Turnover	Tax period		Act	POS (Place of supply)	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
			From	To							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											
Please note that interest has been calculated up to the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.											
You are also informed that if you furnish the return within a period of 30 days from the date of service of this order, the order shall be deemed to have been withdrawn; otherwise, proceedings shall be initiated against you, after the aforesaid period, to recover the outstanding dues.											
						Signature Name Designation Jurisdiction Address					
<b>Note –</b> 1. Only applicable fields may be filled up. 2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory. 3. Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.”.											

13. In the said rules, for **FORM GST ASMT-15**, the following FORM shall be substituted, namely:—

<b>“FORM GST ASMT - 15</b> <i>[See rule 100(2)]</i>											
Reference No.:						Date:					
To											
_____ (GSTIN/ID)											
_____ Name											
_____ (Address )											
<b>Tax Period :</b>						<b>F.Y. :</b>					
SCN reference no. :						Date :					
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;"><b>Act/ Rules Provisions:</b></div>											
<b>Assessment order under section 63</b> Preamble - << standard >>											
The notice referred to above was issued to you to explain the reasons for continuing to conduct business as an un-registered person, despite being liable to be registered under the Act.											
<b>OR</b>											
The notice referred to above was issued to you to explain the reasons as to why you should not pay tax for the period ..... as your registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 with effect from-----											
Whereas, no reply was filed by you or your reply was duly considered during proceedings held on ----- date(s).											
On the basis of information available with the department / record produced during proceedings, the amount assessed and payable by you is as under:											
Introduction :											
Submissions, if any :											
Conclusion (to drop proceedings or to create demand) :											
Amount assessed and payable :											
(Amount in Rs.)											
Serial Number	Tax Rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											
Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.											
You are hereby directed to make the payment by << date >> failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.											
Signature Name Designation Jurisdiction Address											
<b>Note –</b> 1. Only applicable fields may be filled up. 2. Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory. 3. Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.”.											

14. In the said rules, for **FORM GST ASMT-16**, the following FORM shall be substituted, namely:—

<b>“FORM GST ASMT – 16</b> <i>[See rule 100(3)]</i>											
Reference No.:						Date:					
To											
_____ (GSTIN/ID)											
_____ Name											
_____ (Address )											
<b>Tax Period :</b>						<b>F.Y. :</b>					
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;"> <b>Act/ Rules Provisions:</b> </div>											
<b>Assessment order under section 64</b> Preamble - << standard >>											
It has come to my notice that un-accounted for goods are lying in stock at godown----- (address) or in a vehicle stationed at ----- (address & vehicle detail) and you were not able to, account for these goods or produce any document showing the detail of the goods.											
Therefore, I proceed to assess the tax due on such goods as under:											
Introduction :											
Discussion & finding :											
Conclusion :											
Amount assessed and payable (details at Annexure) :											
(Amount in Rs.)											
Serial Number	Tax Rate	Turnover	Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Others	Total
			From	To							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total											
<p>Please note that interest has been calculated upto the date of passing the order. While making payment, interest for the period between the date of order and the date of payment shall also be worked out and paid along with the dues stated in the order.</p> <p>You are hereby directed to make the payment by &lt;&lt; date &gt;&gt; failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           Signature            Name            Designation            Jurisdiction            Address         </div> <p><b>Note –</b>            Only applicable fields may be filled up.            Column nos. 2, 3, 4 and 5 of the above Table i.e. tax rate, turnover and tax period are not mandatory.            Place of Supply (POS) details shall be required only if demand is created under IGST Act.”.</p>											

**15.** In the said rules, in **FORM GST CPD-02**, for the table and Note below the table, the following table and Note shall be substituted, namely:—

<b>“Sr. No.”</b>	<b>Offence</b>	<b>Act</b>	<b>Compounding amount (Rs.)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)

*Note:- (1) In case the offence committed by the taxable person falls in more than one category specified in Column (2), the compounding amount shall be the amount specified in column (3), which is the maximum of the amounts specified against the categories in which the offence sought to be compounded can be categorized.*

*(2) This amount will be deposited under minor head “Other”.*

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.